उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) 30 अक्तूबर, 1996 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कुल 100 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता दी गई है जिनमें राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 87 तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत 13 केन्द्र हैं।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मान्यता के लिए 13 केन्द्रों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्टों रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय को प्रस्तुत की जानी हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के पास कोई स्थाई समिति की निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

American Laws on Non-Involvement of Child Labour

1771. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India propose to object to American laws regarding stationing of child labour inspectors to ensure non-involvement of child labour; and

(b) if so, the details of the steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) While Govt. of India has no specific information about the proposed US Law, it will be opposed to any extra-territorial laws which may authorise stationing in India of child labour inspectors to ensure non-involvement of child labour.

इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि

1772. **श्री राम जेठमलानी**: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान बिजली की विक्रय लागत रेलवे के भाड़े की दर, पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले के मूल्यों में वृद्धि के कारण इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक कारण से इस्पात की उत्पादन लागत में कितनी-कितनी वृद्धि होने की संभावना का आकलन किया गया है;

(ग) क्या उत्पादन लागत में इस वृद्धि के कारण भारतीय इस्पात अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) जी, हां। अकेले स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में यह अनुमान लगाया गया है कि दिनांक 1.4.1996 से राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा सप्लाई की जा रही विद्युत, रेल भाड़े, पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले के मूल्यों में वृद्धि से इस्पात की उत्पादन लागत पर वार्षिक प्रभाव लगभग 890 करोड़ रुपए होगा।

(ग) और (घ) उत्पादन की लागत के अतिरिक्त भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, भाड़ा लागत, रुपए की विनिमय दर, अन्य देशों में उत्पादन लागत आदि जैसे घटकों द्वारा निर्धारित होगी। ये घटक सामान्यतया गतिशील हैं और बराबर बदलते रहते हैं।

Setting up of a Special Committee by the Indo-Japan Business Cooperation Committee for Industrial Development

1773. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Indo-japan Business Cooperation Committee has set up a special committee for industrial development to facilitate interection between SMEs of both countries;

(b) if so, what are its main functions; and

(c) the extent to which Japan has been able to set up industries in India and also help Indian industry?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) No, Sir. However under the auspices of the Indo-Japan Business Cooperation